सम्पादकीय

विकास के स्थायी लक्ष्य

ऐसे वक्त में जब आम चुनाव सिर पर हैं और उसके कुछ माह बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपेक्षित हैं, हरियाणा का बजट लोकलुभावना होना स्वाभाविक ही था। अपने दूसरे कार्यकाल के इस अंतिम बजट में मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्रालय का भी दायित्व निभाने वाले मनोहर लाल ने हर वर्ग को राहत देने का प्रयास ही किया है। नये कर नहीं लगाए गए और राहत की घोषणाओं का पिटारा खोला गया। जिन वर्गों को प्राथमिकता के रूप में देखा गया, उन्हें खास राहत देने की कोशिश हुई। फसली ऋण पर ब्याज-जुर्माना माफकरने की घोषणा की गई। राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य कवच के रूप में बीमा देने का वादा किया गया। शहीदों के परिजनों को एक करोड़ की मदद देना उनके बलिदान को सम्मान देने का सार्थक प्रयास है। निस्संदेह, बजट में उन वर्गों को तरजीह दी गई है जो डबल इंजन सरकारों की प्राथमिकता रहे हैं। समाज में जिन चार जातियों को नरेंद्र मोदी अपनी प्राथमिकता बताते हैं यानी किसान, युवा, महिला और वंचित समाज, वे ही राज्य सरकार के बजट में अहम रहे हैं।

निस्संदेह, किसी भी लाभकारी योजना या घोषणा के साथ कई तरह के किंतु-परंतु भी होते हैं और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार अपने लक्ष्यों को लेकर प्रतिबद्धता जता रही है। जिसके लिये राज्य सरकार ने विकास योजनाओं का एक खाका भी खींचा है। उसके माइक्रो लेवल पर प्रबंधन की कोशिश भी हुई है।निस्संदेह, आम चुनाव के खुमार की तरफ बढ़ते देश में केंद्र व राज्य सरकारों का बजटीय मकसद लक्षित जनसमूहों को प्रभावित करना ही होता है। हालांकि, आम मतदाता के मन में बजट को लेकर यही प्रश्न होता है कि उसकी जेब किस हद तक प्रभावित होगी। यही वजह है कि सरकारें ऐसे मौके पर नये करों से परहेज करके उजली अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों की तसवीर उकेरने का प्रयास करती हैं। विभिन्न वर्गों को राहत देने की घोषणा इसी मकसद से बजट में की गई है ताकि चुनावी वैतरणी पार करने में यह मददगार साबित हो। बजट में बेरोजगारी की समस्या को संबोधित करते हुए कौशल विकास को राज्य सरकार ने प्राथमिकता बताया है। जिसके लिये स्टार्टअप फंड सार्थक परिणाम दे सकता है। बेहतर होता कि सरकार राज्य में उद्योग व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये अतिरिक्त प्रयास करती। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता भी बजट में दी गई है, जिसके लिये होलिस्टिक हेल्थ को भी महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद व योग को भी तरजीह दी गई है। जिसमें केंद्र की आयुष्मान भारत के साथ राज्य की महत्वाकांक्षी चिरायु योजना को भी महत्व दिया गया है। निस्संदेह, ये योजना कमजोर वर्गों के लिये राहतकारी है,क्योंकि वे कम अंशदान से अधिक लाभ गंभीर रोगों के उपचार में उठा सकते हैं। बहरहाल, किसी भी राज्य सरकार को प्रदेश में स्थायी विकास को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए, जिसके चलते राज्य में स्थायी समृद्धि का मार्ग सुनिश्चित हो।

बेरोजगारी बन रही राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा

ऐसे वक्त में जब देश भर के किसान अपनी फसलों के लिये सम्मानजनक न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर दिल्ली कूच कर रहे हैं और वकील व सिविल सोसायटियां ईवीएम से वोट न कराने के लिये प्रदर्शन कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस मायने में और भी बढ़ती आ रही हैं कि अब देश में चरम पर पहुंच चुकी बेरोजगारी की आंच युवाओं और छात्रों को झुलसाने लगी है। कथित मोदी मैजिक उतरता दिख रहा है क्योंकि युवा जीवन की तल्ख सच्चाइयों से परिचित हो रहे हैं। अगर युवाओं और छात्रों को इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें भावनात्मक मुद्दों के आधार पर बरगलाया गया है तो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुश्किलें आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती हैं जिसकी किसी भी क्षण घोषणा होने का इंतजार देश कर रहा है। नरेन्द्र मोदी का आविर्भाव और उनके तेजी से भारतीय राजनीति में छा जाने के लिये सबसे अधिक जिम्मेदार युवा व छात्र ही थे। आज वही वर्ग उम्र के इस मुकाम पर खड़ा है जहां वह महसूस कर रहा है कि अगर अगले एक-दो वर्षों में उसे नौकरी न मिली तो उसके सामने आजीवन बेरोजगार रहने का खतरा है। 2013 में श्री मोदी को जब भारतीय जनता पार्टी और उनकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था तो उनका सबसे बड़ा समर्थक वर्ग यही युवाओं व किशोरों का था। उनके मन में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के बारे में घृणा भरी हुई थी। गांधी और नेहरू को गालियां देने वाले ऐसे युवाओं का राजनैतिक ज्ञान इतना ही था कि श्अय्याशश् नेहरू ने कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया और अगर उनकी जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो अब तक अखंड भारत बन चुका होता। वे यह भी मानते थे, अब भी कई ऐसे हैं जो ऐसा ही सोचते हैं, कि कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है और मुस्लिम परस्त है। उस वाट्सएप विश्वविद्यालय से आयातित ज्ञान का पाठ्यक्रम विशालकाय है, जिसकी स्थापना इन्हीं लोगों के लिये की गयी है और जिसके सारे अध्यायों को किसी भी अखबार के सीमित पन्नों में नहीं समेटा जा सकता। बहरहाल, देश के 1947 में आजाद होने नहीं वरन उसे 99 वर्षों के लिये लीज पर देने वाला यह वर्ग मौजूदा सरकार के राज में मस्जिदों के सामने नाच-गाकर मजे से समय काट रहा था। कुछ अब भी यही श्क्वालिटी टाइमश् व्यतीत कर रहे हैं। यही वह वर्ग था जो मानता था कि इस महामानव के पास सारी समस्याओं का हल है और वह (मोदी) डॉ. मनमोहन सिंह जैसा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने की बजाय हार्ड वर्क करके चीन और पाकिस्तान को कंपकंपा देगा। राहुल गांधी ने रोजगार का मसला उठाकर उस तालाब में कंकड़ नहीं बल्कि बड़ा सा पत्थर फेंक दिया है जिससे युवाओं-छात्राओं की उनींदी आंखों पर पानी का ऐसा जबर छिड़काव हुआ है कि उनकी आंखें खुलती सी दिख रही हैं। वैसे तो राहुल गांधी ने जब 7 सितम्बर, 2022 से 30 जनवरी, 2023 तक (कन्याकुमारी से कश्मीर) की भारत जोड़ो यात्रा की थी, तब भी बड़ी संख्या में उनसे मिलने युवा आ रहे थे। उन्होंने यह पाया कि जिस व्यक्ति की छवि को जैसा पेश किया गया था, वह वैसा बिलकुल नहीं है। वह न युवराज है न शहजादा। अग्निवीर योजना जब भारत सरकार लेकर आई तभी श्री गांधी ने इसे युवाओं के साथ अन्याय बतलाया था। आज साबित हो चुका है कि देश की सेना तक उससे रजामंद नहीं थी। एक सनकपूर्ण व अदूरदर्शितापूर्वक लिये गये फैसले से छात्रों व युवाओं के करियर को तो नुकसान हुआ ही, सेना को भी अधिकारियों की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 14 जनवरी से निकली उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी असंख्य युवा राहुल गांधी से मिल रहे हैं। अब यह वर्ग जान गया है कि उनके भीतर नफरत और हिंसा इसलिये भरी गयी थी ताकि भाजपा सरकार उनके रोजगार भी छीन ले तो वे उसका विरोध न कर सकें। अब वह यह भी जान गया है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात सिवाय जुमले के कुछ नहीं था। अब वे इस स्थिति में और जीवन के इस पड़ाव में पहुंच गये हैं जिसमें न वे नौकरी के लायक रह गये हैं और न ही पकौड़े बेच सकते हैं। पछतावे व खुल चुकी और आंखों के साथ अब युवा राहुल गांधी के साथ यात्रा के दौरान मंच साझा कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस छात्रों और युवाओं पर डंडे बरसाने में कोई मुरव्वत नहीं करती, वहीं वाराणसी, प्रयागराज आदि में युवा व छात्र राहुल के साथ वाहनों के बोनट और छतों पर खड़े होकर बता रहे हैं कि कैसे यहां प्रश्नपत्र योजनाबद्ध तरीके से लीक कराकर परीक्षाएं ही निरस्त करा दी जाती हैं। कभी मोदी मोदी का समवेत करने वाले युवा अब बता रहे हैं कि कैसे वे अग्निवीर योजना के माध्यम से ठगे गये हैं। युवाओं के जाग्रत होने का ही यह खौफहै कि 17-18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा इसलिये रद्द कर दी गयी क्योंकि उसके पेपर लीक हो गये थे। इसे लेकर राज्य में युवाओं-छात्रों के प्रदर्शन हुए थे। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई सभा में लोगों का अपने हक के लिये लड़ने का आह्वान कर रही थीं। राहुल कह रहे हैं कि वे बब्बर शेर हैं और उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।श् बेरोजगारी का राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनना बेहद शुभ संकेत है।

राहुल, तेजस्वी, अखिलेश : नई उम्मीद जगाते लोग

शकील अख़्तर

बिहार में का बा! नौकरियों की बहार ही बहार बा। और अपने यूपी में? यहीं से करबे जा बा। सब मास्टर, मास्टरनियां बन गए। सरकारी नौकरी। पक्की नौकरी। तनखा पचास हजार से ऊपर। यहां तो पेपर लीक हो रहे हैं। पहले आर ओ (रिव्यू आफिसर) के हुए और अब पुलिस के। यह वह संवाद हैं जो आज उत्तर प्रदेश में घर-घर हो रहे हैं। कितने लोगों ने फार्म खरीदे इसका कोई आकंड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। मगर आम तौर पर जितने लोग फार्म खरीदते हैं उसके आधे ही भरते हैं, एलेजिबल (पात्र) होते हैं। 48 लाख एडमिट कार्ड इशु होने की खबर है। मतलब एक करोड़ युवाओं ने करीब फार्म खरीदे थे। एक फार्म की कीमत 400 रुपए। जोड़ते रहिए हिसाब की सरकार ने कितने पैसे कमा लिए। और वह भी बेरोजगारों से। और यह तो सरकार की आमदनी है। अभ्यार्थियों (केंडिडेंट) का कितना खर्च हुआ। यह उनके बयान सुनिए। जो आज सोशल मीडिया में पचासों वीडियो के रूप में घूम रहे हैं। संक्षेप में हम बता दें फिर अगले मुद्दे पर चलेंगे कि अपने गांव से आकर शहर में कोचिंग की फीस। कमरे का किराया। खाना, किताबों का खर्चा। और फिर परीक्षा देने के लिए आना जाना। यह भी खुद ही जोड़ते रहिए, अगर बेरोजगार के दुरूख को समझना है तो। और इसमें यह तथ्य भी याद रखिए कि लड़के-लड़की के मां-बाप भी गरीब हैं। पुलिस कांस्टेबल (सिपाही) के लिए गरीब निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे ही जाते हैं और वह परिवार किस तरह अपना पेट काटकर बच्चों को पैसे पहुंचाता है इसे आएगा तो मोदी ही चिल्लाने वाले भक्त शायद ही समझ सकते हैं। मगर जैसा कि एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कह रहा है कि मैंने दाल फ्राई नहीं खाई। उबली दाल खाकर काम चलाता रहा कि वर्दी पहन कर गांव जाऊंगा। मगर अब क्या करूं? यह सारी सच्चाइयां और इससे भी ज्यादा कई वीडियो में सोशल मीडिया में चल रही हैं। मगर मुख्यधारा के मीडिया में यह नहीं है। वहां बिहार की कहानियां हैं। तेजस्वी यादव ने दो लाख से ऊपर शिक्षकों को वहां नियुक्त कर दिया। जाहिर है इससे गोदी मीडिया के जंगल राज की सारी धारणा धराशायी हो गई। लालू का लड़का, शिक्षा विभाग उसके दल के पास और बिना एक भी कमी के लाखों टीचरों को नियुक्ति पत्र दे दिया। तहलका मच गया। वीडियो बनाए जाने लगे। बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) के शिक्षकों की जनरल नालेज की परीक्षा चौनल लेने लगे। जो मुंह में आए सवाल कर रहे थे और जवाब न दे पाने पर उन्हें अयोग्य साबित कर रहे थे। उनके खुश होने नाचने-गाने के वीडियों डाल रहे थे कि देखिए क्या कर रहे हैं। खुश होना अपराध बता रहे थे। शायद यह कहना चाह रहे थे कि जब इतना कसा जा रहा है तब जनता इतना खुश कैसे हो सकती है। मगर सच यह है कि उन्हें जब बीपीएससी की परीक्षा में कोई कमी नहीं मिली तो शिक्षकों में ढूंढने लगे और इससे भी आगे का सच यह है कि उस समय के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बेरोजगारों को रोजगार देने के इस काम से पूरी मोदी सरकार हिल गई थी। हम केन्द्र में दस साल से सरकार होने के बाद कई राज्यों में डबल इंजन सरकार होने के बाद नौकरी दे नहीं पा रहे या दे नहीं रहे और इस कल के लड़के तेजस्वी ने लाखों नोकरियां दे दीं। और वह भी बिना पेपर लीक हुए। हमारे मित्र मीडिया को कोई कमी नहीं मिली। नौकरी देने के चक्कर में ही तेजस्वी की नौकरी गई। ऐसे ही लैपटाप बांटकर अखिलेश ने दुश्मन कमाए। जैसे आज केवल बिहार में नहीं देश भर में बिहार में टीचर नियुक्ति की चर्चा हो रही है वैसे ही पहले केवल यूपी में नहीं देश भर में अखिलेश यादव के विद्यार्थियों को लैपटाप बांटने की धूम थी। एक ने छात्रों को पढ़ने के लिए लैपटाप दिए दूसरे ने पढ़ाने के लिए शिक्षक दिए। मगर मीडिया के लिए यह कभी देश को आगे ले जाने वाली खबरें नहीं थी। वह तो इस भाषण को छापता है टीवी पर डिबेट करता है कि कांग्रेस ने देश के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया। नेहरू ने आईआईटी, एम्स दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान बनाए राजीव गांधी ने नवोदय स्कूल जो गांव में होता है और पूरी तरह रेजिडेंशल (छात्रों को वहीं होस्टल में रखकर, खाने-पीने की व्यवस्था सहित) की बिल्कुल नयी अवधारणा। और फिर यह जो अखिलेश के लैपटाप देने का एकदम आगे का कदम और तेजस्वी के सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता के साथ योग्य शिक्षकों की नियुक्ति न प्रधानमंत्री मोदी को देश का भविष्य बनाने वाले लगते हैं और न मीडिया को। उन्हें तो पकौड़े तलने से रोजगार आता है यह देश को विश्व गुरु बनाने की बात लगती है। उन्हें लगता है कि बड़ी-बड़ी बातें बनाने से दुनिया में देश का सम्मान बढ़ गया। नेहरू, इन्दिरा के बड़े-बड़े कामों से देश का नाम नीचे गिरा है। दरअसल अब लड़ाई बातों की बादशाहत और काम की कर्मवीरता के बीच हो गई है। बेरोजगारी देश की सबसे भयावह समस्या है। मगर भाजपा के लिए और उसके मित्र मीडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या देश में भाईचारे का माहौल और रोटी के बारे में सोचना है। दोनों मिलकर नफरत और विभाजन को इस स्तर तक बढ़ा चुके हैं कि किसान जिसे वे खुद अन्नदाता कहते थे अब गुंड़ा, मवाली, खालिस्तानी, देशद्रोही हो गया है और जनता जो अधिकार मांगे वह निकम्मी। इंडिया गेट पर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। जन अधिकार पथ नहीं। पहले मीडिया किसी भी समस्या जनता की परेशानी में सरकार से, प्रशासन से सवाल करता था। उसकी अनदेखी, गलतियां बताता था। आज जनता की बताता है। कोविड तक में गलती जनता की बताई जाती रही। जब ज्यादा समस्या आई तो व्यवस्था की बता दी। मगर क्या मजाल है सरकार पर एक ऊंगली भी उठाई हो। उल्टा उसके ताली थाली बजाकर कोरोना को भगाने की दिल खोलकर प्रशंसा की।वह तो चुनाव हैं। तो यूपी में पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी। नहीं तो अग्निवीर की भर्ती तो बंद हुई नहीं। देश भर के युवाओं ने उसका विरोध किया। फौज के तमाम जनरलों ने इसे सेना के लिए बेहद खराब योजना बताया। मगर अग्निवीर चालू रही। यूपी में संख्या बड़ी थी। 48 लाख युवा ने परीक्षा दी। मतलब हर जिले के हजारों लड़के लड़कियां। इतने आक्रोश को भाजपा सहन नहीं कर सकती थी। और उस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं जब यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता हो गया है। एक और एक मिलकर ग्यारह होने का माहौल बन गया है। अस्सी सीटें हैं यूपी में। जिस और झुक जाएंगी उधर ही सरकार बन जाएगी। राहुल की यात्रा यूपी में बहुत फलदाई रही। रविवार को यूपी में आखिरी दिन था और इस दिन अखिलेश यादव ने यात्रा में शामिल होकर यात्रा को और चमका दिया। ये सब भविष्य के चेहरे हैं। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, उद्धव, स्टालिन, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, ममता आदि। सबके पास भारत के भविष्य की और युवाओं को आगे ले जाने की परिकल्पना है। योजना है और जिसको भी जब मौका मिला है उसने इसे बताया है। इस बार इस सम्मिलित शक्ति का मुकाबला करना केवल बातों से कैसे संभव होगा देखने का मजेदार मौका मिलेगा।

मोदी की मंदिर यात्राएं वि-उपनिवेशीकरण नहीं है

राम पुनियानी

हाल (22 जनवरी 2024) में अयोध्या के राममंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के अवसर पर अत्यंत भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों, विशेषकर उत्तर भारत, में धार्मिकता के सामूहिक प्रदर्शन हुए। इस अवसर पर हमने देखा कि राजनैतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता दोनों मानों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में केन्द्रित हो गईं। अयोध्या के बाद मोदी ने अबू धाबी में एक बड़े मंदिर (श्री स्वामीनारायण) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भी जमकर जश्न मनाया गया और इसका खूब प्रचार-प्रसार हुआ। और अभी कुछ दिन पहले मोदी ने उत्तर प्रदेश में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। मंदिरों से जुड़े इन उत्सवों की श्रृंखला से प्रभावित कई दक्षिणपंथी चिन्तक दावा कर रहे हैं कि मोदी पहले ऐसे राजनेता हैं जो किसी उत्तर-औपनिवेशिक समाज की संस्कृति का वि-उपनिवेशीकरण कर रहे हैं। उपनिवेशवाद का दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ा? दक्षिण एशिया का समाज मूलतरू सामंती था जहां जमींदार और राजा शासन करते थे और पुरोहित वर्ग उनके राज को उचित बताता था। ब्रिटेन दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्से, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप, को अपना उपनिवेश बनाने में सफल रहा। अंग्रेजों का जोर यहां की संपत्ति को लूटने और भारत को इंग्लैंड में उत्पादित माल के लिए विशाल बाजार के रूप में इस्तेमाल करने पर था। इसके लिए उन्हें यहां एक औपनिवेशिक राज्य का ढांचा खड़ा करना पड़ा। उन्हें परिवहन और शिक्षा की सुविधाएं विकसित करनी पड़ीं और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था कायम करनी पड़ी। ब्रिटिश शासकों ने सती जैसी कुछ भयावह प्रथाओं के उन्मूलन का समर्थन किया मगर जहां तक बड़े सुधारों और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रश्न है, उनके लिए जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले, आंबेडकर और गाँधी जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ा। किसी भी समाज की संस्कृति स्थायी नहीं होती। वह निरंतर परिवर्तनशील होती है। औपनिवेशिक शासनकाल में भी देश में कई तरह के सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। पश्चिम का अन्धानुकरण, इन सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक छोटा भाग था। जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वह था- समानता पर आधारित समाज की ओर यात्रा की शुरुआत। इसके अलावा, भारत ने आधुनिक-औद्योगिक सामाजिक संस्कृति की ओर धीरे-धीरे कदम बढ़ाना शुरू किये। ये परिवर्तन मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और आरएसएस जैसे दकियानूसी राजनैतिक संगठनों को पसंद नहीं थे। वे इन्हें पश्चिमी बताते थे। असल बात यह थी कि वे पददलित लोगों को समान दर्जा देने की ओर यात्रा के खिलाफ थे और ऐसे प्रयासों पर उन्होंने श्पश्चिमीश् का लेबल चस्पा कर दिया। इसी तरह, उन्होंने भारतीय संविधान, जो भारत की राजनैतिक संस्कृति का मूर्त रूप था, को पश्चिमी मूल्यों पर आधारित बताया। हिन्दू दक्षिणपंथी विचारक हर उस विचारधारा के धुर विरोधी थे जो समानता की बात करती थी। वे श्मनुस्मृतिश् जैसी धार्मिक संहिताओं की शान में गीत गाते थे, जो जातिगत और लैंगिक ऊंच-नीच की हामी थीं। यह दिलचस्प है कि जिन सामाजिक शक्तियों ने पश्चिम-विरोधी नैरेटिव का निर्माण किया, उनकी जड़ें सत्ता के सामंती ढांचे में थीं। इसके साथ ही वे औपनिवेशिक शासकों की सहयोगी थीं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय आन्दोलन देश की संस्कृति को आकार दे रहा था और साथ ही औपनिवेशिक शासकों का विरोध भी कर रहा था। इस सिलसिले में पश्चिम एशिया के मुस्लिम ब्रदरहुड का उदाहरण प्रासंगिक है। वह भी प्रजातान्त्रिक मूल्यों और संस्कृति को पश्चिमी बताता है और इस्लाम के नाम पर सामाजिक असमानता और अधिनायकवादी नियम लादना चाहता है। भारत में भी हिन्दू दक्षिणपंथ समानता का विरोधी है और उसे पश्चिम से आयातित संकल्पना बताता है। भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के विरोध को औपनिवेशिक संस्कृति के विरोध का जामा पहनाया जाता है और यह कहा जाता है कि इससे भारतीय संस्कृति गौरवान्वित होती है। दरअसल, जिसे औपनिवेशिक संस्कृति का विरोध कहा जाता है वह न्याय और बंधुत्व पर आधारित संस्कृति का विरोध है। जाति और लिंग से ऊपर उठकर सभी के लिए न्याय, उभरते हुए भारतीय प्रजातंत्र का लक्ष्य रहा है. इस प्रजातंत्र में बहुवाद और विविधता के लिए जगह है। अभी कुछ दशक पहले तक हम शान से कह सकते थे कि भारत की उत्तर-औपनिवेशिक यात्रा अन्य सभी पूर्व उपनिवेशों से बेहतर रही है। इसकी संस्कृति में निरंतरता और परिवर्तन दोनों के लिए स्थान था। गांधी, नेहरु, सुभाष और मौलाना आजाद जैसे लोगों ने जिस जीवन पद्धति की हिमायत की वह भी प्रजातान्त्रिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती थी. वे देश की संस्कृति को प्रजातान्त्रिक मूल्यों के अनुरूप ढालना चाहते थे। वर्तमान में मंदिर से जुड़े उत्सवों की जो श्रृंखला चल रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह वि-उपनिवेशीकरण है! हमें यह भी बताया जा रहा है कि अबू धाबी में जिस मंदिर का उद्घाटन किया गया वह पश्चिम एशिया के श्मुस्लिम देशोंश् में पहला हिन्दू मंदिर है। तथ्य यह कि संयुक्त अरब अमीरात, मस्कट, बहरीन, ओमान आदि में पहली से कई मंदिर हैं। आर्थिक कारणों से भारतीय इन देशों में जाते रहे हैं और इसके साथ ही वहां मंदिर बनते रहे हैं। हमारे आसपास के मुस्लिम-बहुत देशों में भी ढेर सारे मंदिर हैं। बांग्लादेश का ढाकेश्वरी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। पाकिस्तान में भी कई मंदिर हैं और लालकृष्ण अडवाणी ने पाकिस्तान जाकर नवीकृत कटासराज मंदिर का उद्घाटन किया था। हिन्दू मंदिरों के निर्माण के लिए मोदी का महिमामंडन करना ठीक नहीं है। यह कहना एकदम गलत है कि भारत और अबू धाबी में मंदिरों का उद्घाटन कर मोदी के भारत के वि-उपनिवेशीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को समाप्त करने का काम आजादी के आन्दोलन ने किया था। राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ प्रगतिशील सामाजिक कदम उठाए गए, प्रगतिशीत लेखन हुआ और प्रगतिशील थिएटर पनपा। स्वतंत्रता के पश्चात यह प्रक्रिया जारी रही। नेहरु ने वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा दिया तो आंबेडकर ने-आधुनिक मूल्यों पर आधारित संविधान बनाया। वैसे भी भारत कभी औपनिवेशिक संस्कृति में पूरी तरह नहीं डूबा नहीं था। आज भारत में धार्मिकता और दकियानूसीपन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजनीति ने धर्म का लबादा ओढ़ लिया है। हमारी संस्कृति को दकियानूसी और कट्टर मूल्यों से सबसे ज्यादा खतरा है। इसका एक मजेदार उदाहरण है विहिप द्वारा अदालत में सिंह अकबर और सिंहनी सीता को वन विभाग द्वारा एक साथ रखे जाने को अदालत में चुनौती देना! जहां तक अबूधाबी का सवाल है, यूएई सहित पूरा पश्चिम एशिया इस्लामिक कट्टरतावाद से जनित दकियानूसी मूल्यों की जकड़ में है। इस इस्लामिक कट्टरतावाद को अमेरिका ने प्रोत्साहन दिया क्योंकि वह उस क्षेत्र के कच्चे तेल के संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता था। इसी उद्देश्य से अमेरिका ने 1953 में ईरान की प्रजातान्त्रिक ढंग से निर्वाचित मोसादेग सरकार को अपदस्थ किया, जिसके बाद से वहां कट्टरपंथी सरकारें बनती गई। बाद में अमेरिका ने मुजाहिदीनों को प्रशिक्षण देने के लिए पाकिस्तान में मदरसे स्थापित करवाए। उसने अलकायदा को धन और हथियार उपलब्ध करवाए। अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण, पश्चिम एशिया की संस्कृति प्रतिगामी बन गयी। अबू धाबी में एक मंदिर के उद्घाटन से तेल की भूखी ताकतों द्वारा पश्चिम एशिया की संस्कृति को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। मंदिर संस्कृति का एक हिस्सा होते हैं। केवल मंदिरों में आरती करने से संस्कृति नहीं बदलती।

यूपी में दम तोड़ती गठबंधन की सियासत को जिंदा रखने का कारण क्या है?

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक छतरी के नीचे आने के बाद सियासी ऊर्जा से भरे हैं। दोनों दलों का नेतृत्व ऐसा माहौल बनाने में लगा है मानो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 'गेम ओवर' हो गया है। ऐसा ही माहौल 2017 के विधान सभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बनाने का प्रयास किया गया था। दोनों ही मुकाबलों की खास बात यह थी कि बीजेपी को यूपी में साइड लाइन करने की विरोधियों की जंग में समाजवादी पार्टी एक प्रमुख किरदार थी। 2017 का विधान सभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर लड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। दोनों ही बार जब चुनाव नतीजे आये तो गठबंधन दलों का ग्राफ धरातल पर नजर आया। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन यानि बीजेपी प्लस को कुल 325 सीटें मिली थीं। इसमें से अकेले बीजेपी ने 384 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जिसमें 312 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी गठबंधन की अन्य दो पार्टियों में अपना दल (सोनेलाल) ने 11 सीटों में नौ सीटें और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी ने आठ में से चार सीटें जीती थीं। वहीं मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। तब इस गठबंधन को मात्र 54 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को चुनाव में 114 सीटों में केवल सात सीटों पर जीत मिली थी, वहीं समाजवादी पार्टी को 311 सीटों में से केवल 47 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह से बात 2019 के लोकसभा की कि जाये तब सपा-बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। तब भी वैसा ही माहौल बनाया गया था, जैसा 2017 में बनाने की कोशिश की गई थी। परंतु नतीजे इस बार भी बीजेपी के ही पक्ष में आये। समाजवादी पार्टी को मात्र पांच और बसपा को दस सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इतना खराब प्रदर्शन होने के बाद भी यह दल एक क्यों हो जाते हैं ? इसकी वजह है एक उम्मीद ? उम्मीद इस बात की कि मुस्लिम वोटों के सहारे वह बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं क्योंकि इन सबको लगता है कि हिन्दू तो आपस में बंटा हुआ है। इसी के चलते गैर बीजेपी नेता हिन्दुओं पर होने वाले अत्याचार पर चुप्पी साधे रहते हैं, जबकि मुसलमानों के साथ छोटी-सी भी घटना घट जाये तो जमीन-आसमान एक कर देते हैं। याद कीजिये जब सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा भाजपा शासित राज्यों में जरा-सी घटना पर भी सिर आसमान पर उठा लेती हैं। खासकर महिला उत्पीड़न के मामलों को तो यह लोग बेहद ही तीखे अंदाज में उठाते हैं। राहुल-प्रियंका ने कुछ वर्ष पूर्व योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में यूपी के हाथरस मामले को जोर-शोर से उठाया था। तब एक दलित युवती की बलात्कार के बाद हत्या किये जाने की बात सामने आई थी। पहली अक्टूबर 2020 को जब प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रही थीं तो पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के पास उनका काफिला रोक दिया था। तब उन्होंने मीडिया से कहा कि उनकी भी बेटी है, इसलिए एक मां के नाते उन्हें ऐसी घटनाओं से बहुत गुस्सा आता है। प्रियंका ने उन्नाव दुष्कर्म कांड को लेकर योगी सरकार पर जमकर सवाल उठाए थे। इस मामले में उनकी सक्रियता देखते ही बनती थी। एक तो मामला भाजपा शासित राज्य का था, दूसरा आरोपों के घेरे में बीजेपी विधायक था। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए पूछा था कि सरकार को बताना चाहिए कि वो महिलाओं के साथ है या अपराधियों के साथ? इसी प्रकार 21 जनवरी 2022 को यूपी के बुलंदशहर जिले में एक किशोरी की हत्या का मामला सामने आया था। परिजनों का आरोप था कि किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या की गई। प्रियंका गांधी 3 फरवरी 2022 को यूपी के बुलंदशहर पहुंचीं, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। 4 फरवरी, 2024 को सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर प्रियंका गांधी ने उप्र के बांदा में एक जज की मौत के मामले को उठाने में देरी नहीं की और प्रदेश सरकार पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। एक जिम्मेदार नेता और नागरिक के नाते प्रियंका की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और अत्याचार पर मुखरता काबिले तारीफनजर आयी, लेकिन यह दर्द दिखावा था। दरअसल वह शुद्ध रूप से सियासत कर रही थीं क्योंकि प्रियंका गांधी की सारी सक्रियता भाजपा या एनडीए शासित राज्यों में ही दिखाई देती है। उन्हें न जाने क्यों भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर ही गुस्सा आता है, लेकिन जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां महिलाओं के उत्पीड़न के मामले सामने आने पर गांधी परिवार चुप्पी साध लेता है। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस के गांधी परिवार सहित हर छोटे बड़े नेता ने मणिपुर और दिल्ली की केंद्र की सरकार पर तीखी बयानबाजी की। सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया। मोदी से बार-बार पूछा गया कि वह मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन लगभग इसी समय कांग्रेस शासित राज्यों- राजस्थान (अब यहां बीजेपी सरकार है), छत्तीसगढ़ और गैर भाजपा शासित राज्यों- बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल आदि में महिला उत्पीड़न के मामलों में प्रियंका गांधी ने मौन धारण करके रखा। राजस्थान में तत्कालीन गहलोत सरकार के पांच साल के शासन में बलात्कार और महिला उत्पीड़न की घटनाओं की बाढ़-सी आ गई थी। महिला सुरक्षा में नाकाम गहलोत सरकार के कारण राजस्थान में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार, दुराचार और बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं को राजस्थान कभी नहीं भूलेगा, लेकिन गांधी परिवार को यहां न कुछ दिखाई दिया और न ही कुछ सुनाई दिया, परिणाम यह हुआ कि जनता ने ही विधान सभा चुनाव में गहलोत सरकार का उखाड़ कर फेंक दिया। यहां पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की घटना पर कांग्रेस और गांधी परिवार के रवैये की भी चर्चा जरूरी है। जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें सुनकर आत्मा सिहर उठती है। संदेशखाली की कई हिंदू महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर पिछले कुछ वर्षों में रात-रात भर यौन उत्पीड़न और बलात्कार करने का आरोप लगाया है।